for disabled children has suddenly been stopped; if so, the reasons therefor;

, (c) whether any Member of Parliament for Nagpur has bought to the notice of Government;

(d) if so, by when the papers have been submitted by the said institution and reasons for holding up grants; and

(e) by\ when Government prcpo-e to release the grants to the said Sangh?

THE MINISTER OF WELFARE SHRI SITARAM 'KESRI): (a) No, Sir. However in cases 'where recommendations of the State Governments are not received or proposals are incomplete, grant is released only after receipt of requsite information.

(b) The continuing grant for the project for the disabled children being given to he organisation, Ma'tru Seva Sangh, Nagpur has not been stopped.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e) The recommendation of the State Government for the project submitted by the Institution was received On 10-2-95. Grant was, thereafter released for 1994.95 in March, 1995.

National Commission for minorities

6709. SHU K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be plaesed to state:

(a) whether the National Minorities Commission has given its opinion on the Wakf Bill 1993; and

(b) if so, what are the objections raised by 'he National Commission for - Minorities on the Wakf Bill 1993?

THE MINISTER OF WELFARE [SHRI SITARAM KESRI):, (a) Government have received a letter dated 20.3.1995 from the Chairman, National Commission for Minorities.

(b) The Chairman. National Commission for Minorities has stated, inter alia. that the introduction of the Waiif Bill 1993 in the Rajya Sabha be deferred till the broad consultation were held with all those who are interested in the matter.

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाणपत्र

6710. श्री नरेश यादव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई नीति के अंतर्गत जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत बोझिल तथा लम्बी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस कार्य को करने के लिए तथा कम से कम समयावधि में जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के प्रधान तथा मुखिया और शहरी क्षेत्रों में वार्ड आयुक्त को शामिल करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कुमारी माधुरी पाटिल तथा अन्य अपीलकर्त्ताओं बनाम अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, थाने– सिविल अपील सं० 5054, 1994 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक स्तर प्रमाण पत्र जारी करने में राज्य सरकारों की प्रक्रिया में एकरूपता लाने का निर्देश दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय